संकल्पित भारत, सशक्त भारत

भारतीय जनता पार्टी

संकल्प पत्र

लोकसभा 2019

विषय - सूची

01 130 करोड़ भारतीयों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का पत्र — 05

02 भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह का संदेश — 07

03 श्री राजनाथ सिंह का संदेश — 10

04 राष्ट्र सर्वप्रथम — 15
- आतंकवाद पर सुरक्षा नीति
- राष्ट्रीय सुरक्षा
- सैनिकों का कल्याण
- घुसपैठियों की सम्मस्या का समाधान
- तटवर्ती सुरक्षा
- सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल (सीएबी)
- वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला
- जम्मू कश्मीर - धारा 370

05 कृषि और किसान कल्याण-किसानों की आय दोगुनी करना — 17
- किसान कल्याण नीति
- कृषि सहयोगी क्षेत्रों का विकास
- सिंचाई का मिशन मोड पर विस्तार
- कोऑपरेटिव
- कृषि और प्रौद्योगिकी का मेल
- पशुपालन
- नीली क्रांति
- ग्राम स्वराज

06 अर्थव्यवस्था — 21
- विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर भारत
- 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की रूपरेखा
- कर नीति
- वास्तु और सेवा कर
- 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश
- मेक इन इंडिया
- खनन क्षेत्र
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम
- उद्यमशीलता एवं स्टार्टअप
- क्लस्टर सेवाओं के लिए पर्यटन का प्रयोग
- पारदर्शी अर्थव्यवस्था
- अंतरराष्ट्रीय व्यापार

07 आधारभूत संरचना-नए भारत की बुनियाद — 25
- शहरी विकास को प्राथमिकता
- स्वच्छ भारत मिशन
- जल शक्ति
- मार्ग
- रेलवे
- हवाई अड्डे
- तटीय क्षेत्रों का विकास
- उर्जा
- डिजिटल कनेक्टिविटी

08 स्वस्थ भारत — 28
- स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभता
- स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत ढांचा
- टीकाकरण एवं पोषण
- क्षय रोग को समाप्त करना

09 सुशासन — 30
- एक साथ चुनाव
- भ्रष्टाचार मुक्त भारत
- सिविल सर्विस एवं शासन में सुधार
- पुलिस व्यवस्था में सुधार
- न्यायिक सुधार
- संघवाद
- ईज ऑफ़ लिविंग
- विज्ञान एवं तकनीकी
- वन एवं पर्यावरण
- हिमालय
- द्वीप
- केंद्र शासित प्रदेश
- उत्तर-पूर्वी राज्य

10 युवा भारत - भविष्य का भारत — 3
- युवाओं को अवसर
- शासन में युवा
- खेल

11 शिक्षा और कौशल विकास - सबके लिए शिक्षा — 3
- प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा
- उच्च शिक्षा
- कौशल विकास

12 महिला सशक्तिकरण — 3
- महिला-प्रेरित विकास
- महिलाओं को समान अधिकार
- महिलाओं के लिए एक गरिमामय जीवन
- महिलाओं को आरक्षण

13 समावेशी विकास — 4
- सबके लिए न्याय
- सबका विकास
- गरीब कल्याण
- निम्न माध्यम वर्ग को प्राथमिकता
- भौगोलिक समानता के लिए प्रतिबद्धता
- अल्पसंख्यक वर्ग
- वरिष्ठ नागरिक
- दिव्यांगों को सक्षम बनाना
- गोरखा विषय का राजनैतिक समाधान
- श्रमिक वर्ग का कल्याण
- छोटे दुकानदारों को पेंशन
- कारीगरों का कल्याण
- बाल कल्याण
- ट्रांसजेंडर वर्ग का सशक्तिकरण

14 सांस्कृतिक धरोहर — 4
- राम मंदिर
- भारतीय आस्था और संस्कृति का संरक्षण
- भारतीय भाषाई संस्कृति का संरक्षण
- नमामि गंगे - गर्व का विषय
- सबरीमाला
- योग का विश्वस्तरीय विकास
- भारतीय सांस्कृतिक पर्व
- धरोहर दर्शन

15 वैश्विक भारत — 4
- वसुधैव कुटुंबकम
- ज्ञान और प्रौद्योगिकी पर वैश्विक समन्वय
- प्रवासी भारतियों के साथ निरंतर संवाद
- वैश्विक मंचों के माध्यम से आतंकवाद का हल
- बहुपक्षीय सहयोग
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता
- राजनयिक कैडर का सशक्तिकरण

राष्ट्र सर्वप्रथम

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व ने पिछले पांच वर्षों में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर इसी नीति पर हम आगे बढ़ेंगे।

आतंकवाद पर सुरक्षा नीति

01 हमारी सुरक्षा नीति केवल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा विषयों द्वारा निर्देशित होगी। इसके उदाहरण हाल ही में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हैं। हम आतंकवाद एवं उग्रवाद के विरुद्ध "जीरो टॉलरेंस" की नीति को पूरी दृढ़ता से जारी रखेंगे और सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का सामना करने के लिए 'फ्री हैंड' की नीति का अनुसरण करते रहेंगे।

राष्ट्रीय सुरक्षा

02 **अपने सुरक्षा बलों को सुदृढ़ बनाएंगे -** हम रक्षा से जुड़े बाकी उपकरणों एवं हथियारों की खरीद तेज करेंगे। सुरक्षा बलों की हमला करने की क्षमता सुदृढ़ बनाने हेतु सैन्य बलों को आधुनिक उपकरण प्रदान करने के लिए हम सघन प्रयास जारी रखेंगे।

03 **रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे -** रक्षा उपकरणों की खरीद में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार ने पिछले पांच वर्ष में कई प्रभावी कदम उठाए हैं। हमारी सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि सबसे आधुनिक एके-203 स्वचालित राइफल्स बनाने की फैक्ट्री की नींव 'रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया' अभियान के अंतर्गत अमेठी में रखी गई है। हम 'रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया' को और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि रक्षा उपकरणों का स्वदेश में ही निर्माण हो सके। इससे रोजगार सृजन होगा और रक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

सैनिकों का कल्याण

04 हमारी सरकार ने लंबे समय से लंबित 'वन रैंक वन पेंशन' को लागू कर सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों के हितों के प्रति अपने संकल्प को प्रतिबद्धता से पूरा किया। इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हम अपने सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों के पुनर्वास के लिए अधिक प्रभावी ढांचा तैयार करने का वादा करते हैं। इस प्रयास के अंतर्गत सशस्त्र बल के सैनिकों के सेवानिवृत्त होने से तीन वर्ष पूर्व उनकी पसंद के अनुसार ही उनके पुनर्वास की योजना आरंभ कर देंगे। इसमें कौशल प्रशिक्षण, सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा, आवास एवं उद्यम आरंभ करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान शामिल होगा।

पुलिस बलों का आधुनिकीकरण

05 हम केंद्रीय पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाते हुए उनकी कार्य क्षमता और दक्षता में वृद्धि करेंगे, जिससे वह आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का सामना सुदृढ़ता से कर सकें।

06 हम राज्यों की पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए भी अपनी पुलिस आधुनिकीकरण की पुनरीक्षित योजना के अंतर्गत सहायता मुहैया कराएंगे। राज्यों में पुलिस सुधार का कार्य भी तेजी से किया जाएगा, जिससे कि वह साइबर-क्राइम जैसे नए प्रकार के अपराधों से लड़ने में सक्षम हो सकें और नागरिकों, विशेष तौर पर कमजोर एवं असहाय वर्गों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हों।

घुसपैठियों की समस्या का समाधान

07 घुसपैठ से कुछ क्षेत्रों की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान में भारी परिवर्तन हुआ है और स्थानीय लोगों की आजीविका तथा रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसे क्षेत्रों में प्राथमिकता पर एन आर सी का कार्य किया जाएगा। देश में चरणबद्ध तरीके से चिन्हित करके इसे लागू करेंगे।

08 पूर्वोत्तर क्षेत्रों में Illegal Immigration रोकने के लिए प्रभावी प्रयत्न किए जाएंगे। इसके लिए हम देश की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करेंगे। सीमाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए तकनीक के प्रयोग (स्मार्ट फेंसिंग) का पायलट प्रोजेक्ट धुबरी (असम) में लागू किया गया था, उसको हम सभी सीमाओं पर लागू करेंगे।

सीमा सुरक्षा सुदृढ़ करेंगे

09 हम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में विकासात्मक और आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष ध्यान देंगे, जिससे कि ये क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने में और भी अधिक मजबूती से योगदान करने के साथ-साथ, अन्य क्षेत्रों के बराबर, देश की उत्तरोत्तर प्रगति से पूरी तरह और भी अधिक लाभ ले सकें।

10 अपने पड़ोसी देशों से व्यापार एवं यात्रियों के आवागमन में सहूलियत लाने के लिए 6 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण किया गया है और एक निर्माणाधीन है। हम इस कार्य को और आगे बढ़ाते हुए 2024 तक 14 और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण करेंगे, ताकि हमारा पड़ोसी देशों के साथ व्यापार एवं यात्रियों के आवागमन में और अधिक सहूलियत हो सके। इनके निर्माण के बाद अनुमान है कि हमारा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ व्यापार मुख्यतः इन्हीं इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के द्वारा होगा।

तटवर्ती सुरक्षा

11 हम राज्यों में तटवर्ती पुलिस थानों की स्थापना, समुद्री एवं तटवर्ती सुरक्षा सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय समिति की

ग्राम स्वराज

ग्राम स्वराज महात्मा गांधी की भारत की परिकल्पना के प्रमुख स्तंभों में से एक है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी हर किसी को समुचित संसाधन उपलब्ध कराते हुए ग्राम स्वराज का उनका सपना पूरा करने का संकल्प लेती है। 2022 में भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के पवित्र अवसर पर हम महात्मा गांधी की परिकल्पना के अनुसार ग्राम स्वराज के आदर्श को अपनाने का प्रण करते हैं। इस परिकल्पना के अनुसार हम वादा करते हैं:

साश्रय :

हम वर्ष 2022 तक ऐसे प्रत्येक परिवार को पक्का मकान देंगे, जो कच्चे मकान में रहता है या जिसके पास मकान ही नहीं है।

सुजल :

हम 'जल जीवन मिशन' आरंभ करेंगे, जिसके अंतर्गत हम वर्ष 2024 तक प्रत्येक परिवार को पाइप से पानी की आपूर्ति के लिए विशेष कार्यक्रम 'नल से जल' चलाएंगे।

सूचना से सशक्तिकरण :

हम यह सुनिश्चित करेंगे कि 2022 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत हाई-स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जुड़ जाए।

सड़क से समृद्धि :

हम ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षा केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों और बाजारों को गांवों से जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर 'ग्रामीण सड़क उन्नयन कार्यक्रम' आरंभ करेंगे।

स्वच्छता से संपन्नता :

हम तरल अपशिष्ट जल के 100 प्रतिशत निपटान तथा अपशिष्ट जल का पुनर्प्रयोग सुनिश्चित करेंगे।

विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर भारत

5 ट्रिलियन डॉलर के अर्थव्यवस्था की रूपरेखा

01 सन 2014 में भारत को 'फ्रैजाइल फाइव' (पांच कमजोर देशों) में गिना गया था। पांच वर्ष के भीतर भारत ने एक ख्याति अर्जित की, जो न केवल विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है बल्कि आर्थिक रूप से स्थिर भी है। हम विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पहले ही बन चुके हैं और जल्द ही शीर्ष पांच में शामिल हो जाएंगे। हम सन 2030 तक भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि हम सन 2025 तक भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर और सन 2032 तक 10 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लेते हैं।

02 सन 1991 के बाद की सभी सरकारों से तुलना करें तो मोदी सरकार ने पिछले पांच वर्ष में औसत जीडीपी वृद्धि की सबसे अधिक दर (7.3 प्रतिशत) प्राप्त कर दिखाई है और इस दौरान औसत / उपभोक्ता महंगाई की दर सबसे कम (4.6 प्रतिशत)

नए भारत की बुनियाद

आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर ही किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यूपीए सरकार के 10 साल लंबे कार्यकाल में नीतियों के लचर पड़ने और अकूत भ्रष्टाचार से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास पूरी तरह रुक गया था। पिछले पांच साल में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में बुनियादी ढांचे के विकास ने फिर से रफ्तार पकड़ी है। पहली बार भारत इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिक सुविधाओं में वैश्विक मापदंडों के पथ पर अग्रसर है। ग्रामीण इलाकों में सड़क बनने की गति दोगुनी हो गई है और 90 प्रतिशत तक ग्रामीण रोड कनेक्टिविटी हासिल कर ली गई है। इसके अलावा भारत बिजली का निर्यातक देश बन चुका है। आज देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक एवं एलईडी बल्बों का वितरक बन गया है। पोर्ट क्षमता का अभूतपूर्व विकास हुआ है और नई रेल लाइनें को बिछाने में, गेज परिवर्तन और रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण का कार्य दोगुनी गति से हो रहा है। पिछले पांच वर्षों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व निवेश किया है। इसमें रेल, सड़क, स्वास्थ्य और शैक्षणिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। हमने प्रगति 'प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन' नामक नया और विकसित तकनीक-आधारित प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इसके जरिए देशभर के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अटकी हुई परियोजनाओं को गति देने का काम हो रहा है। हमारी पीपीपी व्यवस्था अब निवेशकों के लिए और सुलभ हो गई है।

01 हम गैस ग्रिड, वाटर ग्रिड, आय-वे (I-Way), घरेलू हवाई अड्डों और राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारों पर सुविधा जैसी अगले स्तर की बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देंगे।

02 अधिक-से-अधिक निजी और सरकारी निवेश के साथ हम तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का काम जारी रखेंगे और जमीनी स्तर पर परियोजनाओं के प्रबंधन के माध्यम से जीवन स्तर को बेहतर बनाने और जीवन को आरामदायक बनाने के लिए तत्पर रहेंगे।

03 अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ-साथ इससे रोजगार की कई संभावनाएं पैदा होंगी।

शहरी विकास को प्राथमिकता

04 इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास के जरिए हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उपनगरी बस्तियों और नए शहरी केंद्रों का विकास हो सके।

05 हम शहरी मुद्दों पर उत्कृष्ट पांच स्थानीय केंद्र स्थापित करेंगे। इन केंद्रों के माध्यम से राज्यों एवं स्थानीय इकाइयों को भी शहरी सुशासन और विकास के मुद्दों पर सहयोग प्रदान करेंगे।

06 शहरी मोबिलिटी - हम एक राष्ट्रीय शहरी मोबिलिटी मिशन आरंभ करेंगे जिसका उद्देश्य सभी स्थानीय शहरी निकायों को शहरी मोबिलिटी समाधान प्रदान करना और लोगों को सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग, साइकिल का प्रयोग और पैदल चलने के लिए प्रेरित करना है। इस मिशन के अंतर्गत हम शहरों को सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो, लोकल बस, ऑटो, टैक्सी, ई-रिक्शा सेवा, पैदल पार पथ और साइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके साथ ही हम एक समान मोबिलिटी कार्ड/टिकट के इस्तेमाल को अलग-अलग परिवहन के साधनों के लिए जारी करेंगे।

07 अगले पांच सालों में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि 50 शहरों में मेट्रो का सशक्त नेटवर्क विकसित हो।

स्वच्छ भारत मिशन

08 हमने अपनी प्रमुख योजना 'स्वच्छ भारत मिशन' के अंतर्गत 9 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया। अब हम अपने इस मिशन को नया आयाम देंगे और हर गांव में सतत ठोस कचरा प्रबंधन लागू करेंगे। हम हर गांव, उपनगर और बिना नालियों वाले क्षेत्रों में तरल अपशिष्ट के पूर्ण निस्तारण को मल-प्रबंधन और गंदे पानी के पुनः इस्तेमाल के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे।

09 हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी बस्तियां पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त होने का दर्जा प्राप्त कर लें, और जिन्होंने यह दर्जा प्राप्त कर लिया है, वे इसे आगे भी बनाए रखें।

जल शक्ति

10 पानी बेहद महत्वपूर्ण संसाधन है लेकिन इसका प्रबंधन केंद्रीय स्तर पर भी कई विभागों के माध्यम से होता है। हम जल प्रबंधन के लिए एक नया मंत्रालय बनाएंगे। इस मंत्रालय का उद्देश्य जल प्रबंधन के मसले पर बेहतर प्रयास सुनिश्चित करना और इसे नई दिशा देना होगा। यह मंत्रालय देश के अलग-अलग हिस्सों में बड़ी नदियों को जोड़ने का अटल जी का सोचा हुआ महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को द्रुत गति से आगे बढ़ाएगा जिससे पीने योग्य पानी एवं कृषि सिंचाई समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके लिए एक ऑथिरिटी बनाकर काम की शुरुआत करेंगे।

11 हम 'जल जीवन मिशन' की शुरुआत करेंगे जिसके तहत 'नल से जल' कार्यक्रम के माध्यम से 2024 तक हर घर को नल का पानी उपलब्ध कराएंगे।

12 हम पानी की उपलब्धता में स्थिरता बनाए रखने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण जल संसाधन के संवर्धन और ग्राउंड वाटर

डिजिटल कनेक्टिविटी

34 2022 तक हर ग्राम पंचायत को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। गांवों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान की जाएंगी; साथ ही टेली-मेडिसिन, टेली-एजुकेशन और कृषि आधारित परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा।

स्वस्थ भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य नीति को देश में लागू किया था। इसके साथ ही हमने दवाइयों की कीमत पर नियंत्रण करने और चिकित्सा शिक्षा को विस्तार देने के लिए कई कार्यक्रम बनाए व लागू किए हैं। हम सभी संसाधनों का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिनसे देश में स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में कमी आए और ये आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से आम लोगों की पहुंच में रहें।

स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता

01 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 10.74 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही हमने 2022 तक 1,50,000 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित करने का कार्यक्रम बनाया है। वर्तमान में 17,150 केंद्र स्थापित हो चुके हैं और सफलतापूर्वक चल रहे हैं। अब हम इन केंद्रों की स्थापना के कार्यक्रम को और विस्तार देंगे। इसके साथ ही हम हर गरीब के दरवाजे पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सन 2022 तक टेलिमेडिसिन के प्रावधानों और डायग्नॉस्टिक लैबोरेटरी सुविधाओं (diagnostic laboratory facilities) को लक्षित कर कार्य कर रहे हैं।

02 हम जरूरी यंत्रों की एक सूची तैयार करेंगे और चिकित्सक-यंत्रों की एक अलग मूल्य निर्धारण नीति बनाएंगे, ताकि इनकी कीमतों में कमी आए और सामान्य लोगों के बीच इनकी पहुंच बढ़ सके।

03 हम आरोग्य डेस्क के माध्यम से भारत को चिकित्सा पर्यटन में शीर्ष पर स्थापित करेंगे। हर बड़े शहर में और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आरोग्य डेस्क की स्थापना से इसका प्रचार किया जाएगा, ताकि भारत के चिकित्सा पर्यटन में विदेशी पर्यटकों की दिलचस्पी बढ़े।

स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत ढांचा

04 हमारे प्रयासों से हम आज इस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि देश में हर तीन संसदीय क्षेत्र के बीच एक अस्पताल उपलब्ध है। इस कदम को आगे बढ़ाते हुए हम 2024 तक निजी या सरकारी सहभागिता से हर जिले में एक चिकित्सा महाविद्यालय या स्नातकोत्तर चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करेंगे। आरंभ में 2022 तक ऐसे 75 चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इनके माध्यम से भारत के सब अलग-अलग इलाकों में द्वितीय एवं तृतीय स्तर की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

05 केवल पांच साल में हमने एमबीबीएस में सीटों की संख्या 18,000 बढ़ा दी है, वहीं परा-स्नातक चिकित्सा में सीटों की संख्या 12,000 बढ़ाई गई है। हम चिकित्सा क्षेत्र में और अधिक सुधार लाएंगे तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देने के साथ ही बेहतर व योग्य डॉक्टर बनाएंगे। अपने प्रयासों से हम सन 2024 तक एमबीबीएस और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या को दोगुनी कर देंगे। साथ ही हम पैरा-मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार लाएंगे, जिससे नर्सों, फार्मासिस्टों और अन्य पैरा-मेडिकल स्टाफ की संख्या में बढ़ोतरी होगी।

टीकाकरण एवं पोषण

06 हम राष्ट्रीय पोषण मिशन को एक जन-आंदोलन के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं और सभी आंगनवाड़ी कर्मियों की क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे।

07 मिशन इंद्रधनुष के तहत 3.39 करोड़ बच्चों और 87.18 लाख गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित किया गया है। साथ ही टीकाकरण की वार्षिक दर में 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष से 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई है। 2022 तक हम सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करेंगे।

क्षय रोग को समाप्त करना